नगरपालिकाओं में शहरी बुनियादी सुविधाओं की परियोजना की वित्त व्यवस्था हेतु वित्तीय मध्यस्थ की स्थापना हेतु प्राप्त प्रस्ताव भी विश्व बैंक को भेजा गया है।

(ख)गुजरात में वित्तीय सहायता मुहैया कराने के लिए विश्व बैंक द्वारा किसी नगर पालिका का चयन नहीं किया गया है ।

(ग़)से (ड.) उपर्युक्त भाग (ख) के उत्तर के आलोक में प्रश्न नहीं उठता ।

Raising Capital for Infrastructure Development of Cities

4409. SHRI TARA CHARAN MAJUMDAR: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government's ambitious plan to raise capital for infrastructure development of cities has failed;

(b) if so, whether it is due to faulty planning and inadequate backup from Municipal Bodies;

(c) whether Government propose to take measures for implementation of this plan; and

(d) if so, the details thereof and if not, reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN AFFAIRS & EMPLOYMENT & MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (DR. U. VENKATESWARLU): (a) to (d) No Sir. In order to fund Urban Infrastructure Operations, HUDCO has come out with a public issue of taxable infrastructure Bonds (of 15% p.a.) for an amount of Rs. 200 crores with an option to retain an additional Rs. 50 crores, which has been fully subscribed.

कच्छ जिले में जल-आपूर्ति और जल-माल व्ययन

4410. **श्री अनंतराय देवशंकर दवे :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने गुजरात के कच्छ जिले के मुख्य नगरों में पेय जल आपूर्ति और जल-माल व्ययन परियोजाएं लागू करने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन परियोजाओं को नौवीं पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड) क्या विश्व बैंक अथवा किसी अन्य एजेंसी ने इन परियोजनाओं को सहायता देने का प्रस्ताव किया है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शहरी कार्य और योजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू.वेंकटेश्वरलू) : (क) जी, नहीं

(ख) प्रश्न नहीं उठता

(ग) गुजरात जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड ने सूचना दी है कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

(ड.) जी, नहीं ।

Unauthorised Construction in Government

4411. SHRI MOHINDER SINGH KALYAN:
SHRIMATI MALTI SHARMA:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) the detailas of unauthorised constructions made/being made by allottees in Government Colonies of Laxmibai Nagar, Kidwai Nagar, Sarojini Nagar, Netaji Nagar and R.K. Puram in Delhi;

(b) whether it is a fact that unauthorised encroachments are begin made in connivance with officials of CPWD/NDMC/MCD and Police;

(c) whether the Directorate of Estates had issued notices to the concerned allottees in this regard;

(d) if so, the reasons for not taken any action in the matter; and

(e) the affective measures taker/ proposed to be taken to prevent such